ऐसा प्रश्न आता है कि महाजन अवार्ड पर जोर देते हुए, बार-बार उनकी ओर निदेश करके यह कहा जाता है कि चूंकि महाजन आयोग ने कहा है इसलिये उसको हमें मानना ही पड़ेगा ।

श्री पाटिल ने कहा कि सीमा प्रदेश और पानी के बारे में जो विवाद होता है उसको सुलझाने के लिये हम उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दें । यहां कठिनाई यह है कि जब यह महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद समस्या महाजन साहब को दी गई तब उनको कोई टर्म्स आफ रिफरेंस नहीं दिये गये । जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जायेंगे तब हम लोग कौनसे टर्म्स आफ रिफरेंस देंगे । टर्म्स आफ रिफरेंस तो पार्लियामेंट को ही देने पड़ेंगे । जब भी कोई विधान बनता है तब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे सकता है क्योंकि हमारे संविधान में यह चीज दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट किस-किस विषय पर अपनी राय दे सकता है ।

इसलिये मैं कहता हूं कि महाजन अवार्ड की कीमत कम हो जाती है क्योंकि बुनियादी तत्व जो है, जो टर्म्स आफ रिफरेंस हैं वह उनको नहीं दिये गये । टर्म्स आफ रिफरेंस न देने के कारण हर एक आदमी यही चाहता है कि उसका जो मत है, जो उसका विश्वास है उसको मान लिया जाय ।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया ।

श्री शिकरे : तब फिर मैं समाप्त करता हूं ।

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): Madam Chairman, I rise to support all the demands placed by the Home Ministry.

I am not surprised that Shri S. K. Patil accused this Government for the failure of law and order in every part of the country. Unfortunately, he is not present here. I begin by reading the very first sentence that is in the Introduction of the Report for 1969-70. It says:

> "The trend towards the growth of tension and violence in the country continued and the Ministry of Home Affairs was engaged not only in taking appropriate administratve measures in consultation, where necessary, with State Governments, but also in examining the socio-economic forces that lead to such tensions and violence."

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue his speech tomorrow.

We have now to take up the Half-an-Hour discussion.

Shri Om Prakash Tyagi.

18.29 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

UTILISATION OF PL-480 FUNDS

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मैं आज इस सरकार का ध्यान पी० एल० 480 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यों तो सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित है ही, परन्तु जिस ढंग से होना चाहिये वैसे नहीं है । भारतवर्ष का यह दिन दुर्भाग्य का था जिस दिन उसने आत्म-निर्भरता के सिद्धांत को छोड़कर धन तथा पी० एल० 480 के समझौते को स्वीकार किया । विदेशी सहायता और पी० एल० 480 के धन ने भारतवर्ष को बीस वर्षों में आत्म-निर्भर नहीं होने दिया । मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार की बुद्धिमानी नहीं कि आज देश आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है, अपितु अमरीका के लोगों ने ही इस बात को अनुभव किया कि अगर पी० एल० 480 का अनाज देते चलेंगे तो भारतवर्ष भीख मांगता रहेगा और वह कभी आत्म-निर्भर नहीं होगा । यह कम्युनिस्टों के चक्कर में आ जायेगा ।

[श्री ओमप्रकाश त्यागी]

उन्होंने पी० एल० 480 का अनाज देना बंद करने का संकेत दिया। तब यहां की सरकार को पी०एल० 480 का सहारा छोड़कर अनाज उत्पन्न करने की ओर ध्यान देना पड़ा। पी० एल० 480 का जो अनाज आपने लिया उससे देश में बहुत सी खराबियां पैदा हुई और आगे भी पैदा होने वाली हैं। जो हो चुकीं वे तो हो चुकीं लेकिन आगे के लिए जो खतरा है उसकी तरफ मैं आपका खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे बड़ा नुक्सान पी० एल० 480 से यह हुआ है कि भारतवर्ष का जो किसान है उसमें जो अन्नोत्पादन के लिये उत्साह होना चाहिये था उसको बिल्कुल कुचल दिया गया।

दूसरा यह हुआ कि यहां करोड़ों व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन हुआ पी एल 480 धन के द्वारा। मिजो और नागालैंड के विद्रोह के पीछे भी यही पैसा काम कर रहा है। यहां की राजनीतिक उथल-पुथल में यही पैसा काम आया।

वस्तुओं के मूल्यों में अस्थिरता भी इसी से पैदा हुई। इसके अतिरिक्त राज्य भी केन्द्र पर निर्भर रहने लग गए। कारण यह कि अनाज इनके हाथ में है और राज्य अनाज के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। इस तरह से इन्होंने कटपुतली की तरह से उनको हिलाना शुरू किया।

सदन में लगातार सरकार का ध्यान इन खतरों की ओर दिलाया जाता रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जो ऐग्रीमेंट अमरीका के साथ हुआ उसके अन्दर यह शर्त है कि अमरीका पी० एल० 480 का अस्सी फीसदी पैसा भारत सरकार की सहमति से भारतवर्ष के हित में खर्च करेगा और बीस परसेंट पैसा अमरीकन एम्बैसी द्वारा खर्च किया जायगा और उस पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा।

इस विषय पर राज्य सभा में आधे घंटे की चर्चा हुई थी। और मोरारजी देसाई साहब उस वक्त वित्त मंत्री थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि बीस परसेंट जो धन अमरीकन एम्बैसी के पास है उसके ऊपर भारत सरकार का नियंत्रण न तो है और न ही रहना चाहिये। नियंत्रण नहीं रहना चाहिये, उनके इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं। यह ठीक है कि अमरीका का यह पैसा है और अमरीका इसको खर्च करे। लेकिन अमरीका भारत के हितों के विरुद्ध जाकर इसको खर्च नहीं कर सकता। भारत का हित सर्वोपरि है, अमरीका का हित सर्वोपरि नहीं है। खेद है इस बीस परसेंट धन से देश में भयंकर बरबादी की बात हो रही है। इसमें से अपार धनराशि विदेशी ईसाई मिशनरीज को दी जा रही है। मैं अपनी बात नहीं कहता हूं। बिहार के रेवेन्यू मिनिस्टर का यह स्टेटमेंट है।

"The Bihar Revenue Minister, Mr. Indra Deep Sinha told newsmen that an American Missionary working with one of the Foreign Relief Agencies in the famine stricken Palamu district of Bihar had claimed that an agreement exists between the Governments of India and USA, giving full freedom to missionaries to convert people in the course of famine relief operations."

The claim was made before a Deputy Commissioner of Palamu in July. The Minister gave the name of the missionary as Rev. John. Ralley."

नियोगी कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसने भी उसमें कहा था कि इस धन का दुरुपयोग फारेन मिशनरीज कर रही है स्कूल और अस्पतालों के द्वारा। अमरीकन एम्बैसी के एक कार्यकर्ता जोकि भाग कर मास्को चले गए थे उन्होंने यह रहस्योद्घाटन किया था

कि नागा विद्रोहियों ग्रादि को ग्रमरीकन एम्बैसी से रुपया ग्रौर सहायता मिलती है। पी० एल० 480 के पैसे से भारत में विदेशी क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों का धर्म परिवर्तन करने का ही काम नहीं कर रही हैं अपितु धर्म परिवर्तित व्यक्तियों को देश-द्रोही बना रहे हैं, उदाहरणार्थ मिजो ग्रौर नागालैंड में ऐसे ही ग्रराष्ट्रीय तत्व भी सक्रिय हैं। इस वास्ते यह एक चिन्तनीय विषय है।

प्रो० एम० एल० खुसरो के नेतृत्व में एक ग्रध्ययन दल पी एल 480 की जांच के लिये गवर्नमेंट ने बनाया था। उसने भी इस बात को स्वीकार किया था कि पी० एल० 480 का जो धन है इससे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उसने कहा था कि ग्रब तक तो इनफ्लेशन नहीं हुग्रा है लेकिन जब ग्राप पी० एल० 480 के ग्रन्तर्गत वस्तुएं मंगाना बन्द कर देंगे ग्रौर उसमें धनराशि एकत्रित हो जाएगी तो उसके पश्चात इस देश में इनफ्लेशन का खतरा पैदा हो जाएगा, यहां मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी बात उसने कही थी कि यहां पर मूल्यों में ग्रस्थिरता ग्राएगी बल्कि ग्रगर दुर्भाग्य से इस देश में फसल ग्रच्छी नहीं हुई तो ग्रापको डिफिसिट बजट बनाना पड़ेगा ग्रौर वस्तुग्रों के मूल्य ग्रधिक बढ़ते हुए चले जायेंगे। इस प्रकार जो हमारा ग्रार्थिक ढांचा है वह पूरा का पूरा लड़खड़ा जाएगा। उसने सिफारिश की थी कि इसी वक्त गवर्नमेन्ट को ग्रमरीका के साथ इस मामले को तय करना चाहिये। उसने तीन सुझाव दिये थे। एक तो यह कि ग्रमरीका के साथ एग्रीमेन्ट किया जाना चाहिये कि ग्रस्सी परसेन्ट जो खर्च होता है वह भारत सरकार की सहमति से इस रूप में व्यय होना चाहिये ताकि भारत सरकार ग्रपने बजट में इस प्रकार से उसका एडजस्टमेन्ट कर सके ताकि मूल्यों में वृद्धि न होने पाए। दूसरा यह कि भारत सरकार को ग्रमरीका का पी० एल० 480 का धन ग्रनुदान में ले लेना चाहिये ताकि उस पर भारत सरकार का कंट्रोल हो जाए। तीसरा सुझाव यह दिया था कि इस धन को फ्रीज कर दिया जाए। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो तीन सुझाव उसने दिये थे ग्रौर जिन खतरों की ग्रोर संकेत किया था उससे बचने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं।

ग्रभी फरवरी में ग्रमरीकी सैनेट की विदेश विभाग कमेटी के दो मेम्बर यहां ग्राए थे। उन्होंने ग्रपने दौरे के दौरान कहा था ग्रौर भारत सरकार पर दोषारोपण भी किया था कि इस धन के प्रयोग के लिए ग्रमरीका भारत को जो योजनायें पेश करता है भारत सरकार का एक ही काम है कि उनका विरोध करे। उसने ग्रभी तक कोई भी योजना ग्रपनी ग्रोर से प्रस्तुत नहीं की है। ग्रमरीका की सरकार का यह ग्राक्षेप था कि हमने बहुत सी योजनायें पेश की हैं कि यहां पर मकान बनाये जायें, सड़कें बनाई जायें लेकिन भारत सरकार ने उनका विरोध तो किया लेकिन कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिये। उनका सुझाव था कि भारत सरकार योजनायें उनके सामने उपस्थित करे जिन पर ग्रमरीका विचार कर सके।

मैं जानना चाहता हूं कि ग्रब तक पी० एल० 480 का जो धन ग्राया है, वह कुल कितना ग्राया है। ग्रस्सी प्रतिशत जो भारत में व्यय होना था वह किस-किस मद में भारत सरकार ने व्यय किया है ग्रौर कितना ग्रापको लोन दिया गया है, कितना दान दिया गया है। बीस प्रतिशत जो ग्रमरीका की एम्बैसी ने खर्च करना था ग्रौर जिस पर ग्रापका कोई कंट्रोल नहीं, उसमें से उसने कितना निकाल लिया है ग्रौर कितना बाकी है ? इस धन में से ग्रमरीकन एम्बैसी ने कुली फंड में कितना धन दिया है ?

पी० एल० 480 के ग्रन्तर्गत जब ग्राप

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

अनाज लेना बन्द कर देंगे तब भारतवर्ष के किसानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उस समय मुद्रा स्फीति होने का जो भय है, उसको रोकने के लिए सरकार ने कौनसा उपाय सोचा है ?

अमरीका के पास जो बीस प्रतिशत धन हैं जिसका यहां के राजनीतिक ढांचे में और चुनावों में खर्च किया जाता है और विदेशी ईसाई मिशनरीज के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है, यहां के अराष्ट्रीय तत्वों पर खर्च किया जाता है, उसको कंट्रोल करने के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसका क्या उपाय सोचा है ? क्या आपने अमरीकन सरकार से इस प्रकार की मांग की है कि जो धन इस बीस परसेंट में से आप अमरीकन एम्बैसी के अलावा और किसी चीज पर खर्च करना चाहते हैं, वह हमारे देश के हित में खर्च करना चाहिये और राष्ट्रीय और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उसको खर्च किया जाना चाहिये और वह किसी खास सामाजिक संस्था को न दिया जाय ?

क्या सरकार के सामने कोई इस प्रकार की योजना है कि अमरीकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर पी० एल० 480 के धन का प्रयोग वह कर सके ? क्या कोई ऐसी स्कीम बनाई है या क्या इस प्रकार का आपका विचार है कि भारत में जो पिछड़े हुए लोग हैं, हरिजन आदि हैं, उनके उत्थान के लिए इसको खर्च किया जाए ?

क्या सरकार अमरीकन एम्बैसी से मिल कर एक रिवाल्विग फंड क्रीएट करायेगी, जिसके द्वारा हरिजनों और आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल किया जाये और उनके लिए मकानों और पीने के पानी की व्यवस्था की जाये ?

क्या सरकार अमरीकन एम्बैसी के सामने यह सुझाव रखेगी कि एक रिवाल्विग फंड बना कर इस देश में प्राइमरी एजूकेशन का विस्तार किया जाये ?

सरकार खुसरू कमेटी के तीन सुझावों में से किस सुझाव को स्वीकार करने और उस पर अमल करने का विचार रखती है ?

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : सभा-पति महोदया, पी० एल० 480 के अन्तर्गत हमारे देश में जो अन्न आता है, उसके लिये दिये गये पैसे से यहां के अराष्ट्रीय तत्वों को जिस तरह प्रोत्साहन मिल रहा है और जो खुराफातें हो रही हैं, हमारे माननीय मित्र, श्री त्यागी, ने उसका एक नग्न चित्र आपके सामने पेश किया है। उसे मैं दोह-राना नहीं चाहता। लेकिन उससे देश का जो सबसे अधिक नुक्सान हुआ है, वह है उसके स्वाभिमान का हनन। हम पेट के लिये अमरीका के सामने हाथ पसारते हैं, उससे कर्ज लेते हैं, भीख मांगते हैं। इससे तो कहीं अच्छा था कि हमारी कुछ जनसंख्या ही कम हो जाती और यह सरकार जिनको खिला नहीं सकती, उनका खात्मा कर देती। यह सरकार जनसंख्या को कम करने के लिए भ्रूण-हत्या और गर्भपात सरीखे जघन्य कार्यों की वकालत कर रही है। इससे तो अच्छा था कि वह कुछ लोगों को खत्म कर देती, ताकि हमें पेट के लिए दूसरों से भीख न मांगनी पड़ती। मेरे नाम के एक पुराने कवि हुए हैं श्री वेणी कवि। उन्होंने कहा था : "पेट क्यों न भयों तू दीठ, भूखे मान गवावहिं," इत्यादि मैं नहीं समझता कि इस पेट के लिए सरकार का दर-दर की ठोकरें खाना कहां तक उचित है।

हमारे पिछले प्रधान मंत्री, प्रातः स्मर-णीय स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, ने इस समस्या का समाधान अपने ढंग से किया था। उन्होंने प्रत्येक सोमवार को आधा दिन भोजन

बन्द करने की सलाह दी थी। लेकिन यह उसकी कोई नई सूझ नहीं थी। पहले भी हमारे ऋषियों ने इस समस्या का समाधान किया था व्रतों और उपवासों का धर्म में समावेश के द्वारा। अगर एकादशी का व्रत रखा जाये, तो वर्ष में 24 दिन का अन्न तो यों ही बच जाता है। इसके अतिरिक्त रामनवमी, जन्माष्टमी आदि कई और व्रत और उपवास हैं। अगर हम समूचे राष्ट्र को उन दिनों भोजन न करने की सलाह दें, तो मैं समझता हूं कि उससे भोजन की समस्या तो अपने आप ही हल हो जायगी और पी०एल० 480 सरीखे समझौते से हम सदा के लिए मुक्ति पा सकेंगे साथ-साथ लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तथा इसके साथ ही परिवार-नियोजन की भी जरूरत नहीं रहेगी।

स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो पथ दिखाया था, क्या मंत्री महोदय उसका पुनरुद्धार करते हुए राष्ट्र को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि भिक्षा और कर्ज मांगने के बजाये महीने में कम से कम एक दो दिन का भोजन बन्द करना ही अच्छा है ताकि हमारी अन्न की समस्या सदा के लिए हल हो?

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर): सभापति महोदया, मैं पी०एल० 480 एग्रीमेंट को एन्टी-पीपल और एन्टी-फार्मर मानता हूं। मैं समझता हूं कि वह हमारे देश पर एक बहुत बड़ा ब्लो है, जिसके कारण हमारा देश खुराक के मामले में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है। पी० एल० —480 से जो करेन्सी बढ़ेगी उससे किमतें बढ़ेंगी। जैसा कि श्री त्यागी ने कहा है, पी०एल०—480 का बहुत सा पैसा अनडेजायरेबल एक्टिविटीज में लगता है। लेकिन इस बारे में मेरा मुख्य एतराज यह है कि इस एग्रीमेंट के तहत जो गेहूं या अनाज आता है, वह केवल अमरीकन शिप्स से आता है और उसका सारा पेमेंट डालर्ज में करना पड़ता है। अगर शिप पोर्ट में खड़ा है और लोडिंग में देरी हो गई है, तो हैवी पिनेल्टी लगाई जाती है और वह पिनेल्टी भी डालर्ज में होगी। इसके अलावा शिप्स का किराया भी नार्मल इन्टरनेशनल मार्केट से दो गुना है।

इस व्यवस्था के कारण देश की शिपिंग इंडस्ट्री खत्म हो गई है। जहां तक अमरीका के शिप्स का संबंध है, उनमें से 86 परसेंट शिप्स बहुत पुराने हैं, जो कि 1940 में सेकन्ड वर्ल्ड वार के दौरान केवल तीन महीने के लिए बनाए गए थे। अमरीका के केवल 14 परसेंट शिप्स नये हैं। जो शिप्स केवल तीन महीने के लिये बनाये गये थे, वही शिप्स अनाज लाने के लिए आज तक काम में आ रहे हैं। वे शिप्स पी० एल०—480 के पैसे के कारण चल रहे हैं। एक इकानोमिस्ट ने अनुमान लगाया है कि पी०एल०—480 के अन्तर्गत हमारा देश जो डालर अमरीका को देता है, हमको उनका भाव साढ़े सात रुपये के बजाये अठारह रुपये देना पड़ता है, जबकि ब्लैक मार्केट या ओपन मार्केट में डालर का भाव बारह रुपये है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पी०एल०—480 एग्रीमेंट को इम्मीडिएटली, तुरन्त, कैन्सल कर देगी। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है—जैसी कि मुझे आशंका है, क्योंकि यह सरकार दब्बू सरकार है और वह बाहर के किसी प्रैशर का मुकाबला नहीं कर सकती है—, तो क्या मंत्री महोदय कम से कम यह विश्वास दिलायेंगे कि सरकार कोई नया एग्रीमेंट नहीं करेगी? सरकार हर महीने नया एग्रीमेंट करती है और देश की आत्म-निर्भरता को समाप्त कर रही है।

सरकार ने फारेन आयल कम्पनीज के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है, यहां पर बार-बार मांग की जाती थी कि उस एग्रीमेंट की शर्तों को बदला जाये, लेकिन मंत्री महो-

[श्री कंवरलाल गुप्त]

दय कहते थे कि एग्रीमेंट को नहीं बदला जा सकता है। हमने देखा कि जब सरकार ने दबाव डाला, तो वे कम्पनीज उन शर्तों को बदलने पर तैयार हो गई। उसी तरह क्या सरकार पी०एल०–480 एग्रीमेंट को बदलेगी, ताकि उसमें यह जो कम्पलशन है कि अमरीका के शिप्स के द्वारा ही माल आयेगा, उसको हटा दिया जाये। यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि इंडियन शिप्स से, या जिस तरह भारत सरकार चाहे, उस तरह, माल आये। मैं इस बारे में मंत्री महोदय का केटेगारिकल एश्योरेंस चाहता हूं।

जहां तक रुपये का सवाल है, मैं चाहता हूं कि वह फ्रीज हो जाये और दस साल के बाद उसकी पेमेंट होनी चाहिए।

श्री शशि भूषण (खारगोन) : क्या यह माननीय सदस्य की व्यक्तिगत राय है या जनसंघ की राय है कि पी. एल–480 के रुपये को जब्त कर लिया जाये ?

श्री कंवरलाल गुप्त : यह मेरी पार्टी की राय है।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): As many times before, I am again standing before the Central Government with a begging bowl for the dying city of Calcutta. Calcutta contributed immensely to the nation and in turn it has turned out to be a breeding ground of chaos, violence, poverty, squalor and disease, and also anti-national gangsterism. The Central Government, and the people of India, I should say, have failed to understand the ills and problems of Calcutta. On a previous occasion, I asked the Finance Minister whether a sizeable portion of PL-480 funds will be diverted, as has many times been demanded by the Metropolitan Development Council and also other organisations, for the development of Calcutta. But at that time our Minister pointed out that if that Fund is diverted for the development of Calcutta there would be possibilities of inflation, but fortunately on another occasion the Prime Minister said on the floor of this House that the matter was under investigation. I would again repeat that I am standing here with a begging bowl for the dying city of Calcutta. I would request that a sizable quantum of PL 480 funds should be diverted for salvaging the dying city of Calcutta. I want to know whether the Government will do it.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैडम-चेयरमेन, मैं आपकी मारफत मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा यह पी० एल० 480 नहीं है, यह हिन्दुस्तान पर अमरीका का फंडो है, जिससे हमारे देश की तौहीन होती है। इसलिए इस देश की इज्जत बचाने के लिए आप कौनसी तारीख से इसको बंद करेंगे ? अगर आप मजबूर हैं, कोई एग्रीमेन्ट है या कोई इन्टरनेशनल आब्लीगेशन है, बारगेनिंग है, तो आप इस रुपये का इस्तेमाल इस तरह से करें जिससे बेचारा गरीब किसान भी न मरे, शिपिंग का भी नुकसान न हो और वह आब्लीगेशन भी पूरी हो जाये।

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): Today I have the greatest pleasure to give my full support to all that was said by my Jana Sangh friend on this question. They were declaring all these years that they were going to stop import of foodgrains under the PL 480 agreement. This declaration is being made year after year. I should like to know from the Government whether they can give us a definite time limit, a definite date, by which they are going to completely stop the import of foodgrains under PL 480.

श्री शशि भूषण : मैं मंत्री महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि पी० एल० 480 का बाहर से आनेवाला जो रुपया है, यह बन्द होना चाहिए, बल्कि अगर हो सके तो जो रुपया यहां है, उसको जब्त किया जाये। श्री कंवर लाल गुप्त की इस बात से मैं सहमत हूं और खास तौर से मैं आज यह जानना चाहता हूं कि गेहूं के अलावा क्या कोई और भी खाने का सामान पी०एल० 480 के जरिये हिन्दुस्तान

में आता है ? हम कब तक पी० एल० 480 के इस शर्मनाक तरीके पर डिपेण्ड करेंगे, हम कब इससे आजाद होंगे। कंवर लाल गुप्त की तकरीर सुनने के बाद मैं तो यह कहूंगा कि यह पी० एल० 480 नहीं है, बल्कि पी० एल० 420 है।

SHRI S. KUNDU (Balasore): I would like to know form the Minister whether it is a fact that the Government took up this issue with the American Government from time to time to change this Agreement and whether there was any recent meeting regarding this to change the terms of the Agreement to suit the needs of our country, and if so the latest reaction of the American Government. 20 per cent of the money is reserved to be spent by the American Embassy. Has any account of the expenditure of this money ever been called for and looked into by the Government ?

SHRI P. C. SETHI: The hon. Member Shri Tyagi asked details of PL-480 funds. The total rupee accruals from PL-480 imports from 1956 till December, 1969 available for each purpose were:

Loans to Government	—Rs. 1363.44 crores
Grant to Government	388.49 crores
Cooley loans to Indo-Us enterprises	138.74 crores
Money for Us uses	283.72 crores

These have been the accruals from 1956 to Dec. 1969.

Out of these accruals, the actual expenditure is: loans given to Government. Rs. 1300.25 crores; grants given to Government Rs. 351.15 crores, Cooley loans disbursed Rs. 75.40 crores and money used for U.S. uses Rs. 233.14 crores. The balance left after these expenditures is Rs. 214.45 crores. In addition rupees have accrued from repayments on loans. Repayment and interest payment accured to the U.S. from PL-480 loans are of the order of Rs. 177.76 crores and on non PL-480 loans (because there were certain dollar loans upto 1962 which were also repaid in rupees), Rs. 246.52 crores; interest on special securities is Rs. 109.90 crores. Hence, the total amount which remained with the United States on 31-12-1969 was Rs. 748.63 crores. Out of these, a sum of Rs. 163 crores has been earmarked for loans and grants to Government and for Cooley loans, etc. The balance left is of the order of Rs. 586 crores and this entire amount is invested in Government of India securities, except for a sum of about Rs. 63 crores which is deposited in the three U.S. banks here, as time deposits.

Imports under PL. 480 started at a time when there was a critical shortage of certain commodities and we were also short of foreign exchange. This was a source and the money was to be repaid in rupees. Even now those imports are continuing according to PL-480 agreements.

Shri Shashi Bhushan asked: what are the commodities which are being imported? Soya Bean oil is imported; milo is imported, wheat and cotton are imported. I have given the total value of imports from 1956.

To answer the question of Shri Vasudevan Nair, as far as import of PL. 480 food grains is concerned, the Government of India and the Food Ministry have declared before and it is known to the hon. Members that it is the earnest desire of the Government not to import foodgrains after 1971. That is the position so far as the import of foodgrains is concerned.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आपने इन्दौर में अपने भाषण में कहा था कि 72 तक बंद करेंगे लेकिन यहां पर 71 कह रहे हैं तो इसमें से कौनसा सही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैंने कहा आफ्टर 1971 तो 1971 के बाद 1972 ही आता है।

But as far as the import of soya-bean oil and cotton is concerned, it would depend upon the requirements of the country. We are trying our best to improve the quality and quantity of cotton; and about the oil requirements also, we are trying to improve the position of production. But it would depend upon the requirements of the country.

[Shri P. C. Sethi]

19 hrs.

It was surprising that in one breath Mr. Tyagi was speaking against PL-480 funds. Mr. Vasudevan Nair was not here when Mr. Tyagi was speaking. In the same breath, instead of rejecting it or being against it, Mr. Tyagi was saying, "Why not take the entire amount as grant." This is a queer position, where one is opposed to the grant and then asks, "Why not go with the begging bowl and say that the entire amount should be converted from loans into grant." The Government of India has not come to a position where we would not like to fulfil our commitments. We are not functioning like those countries who had certain loans and agreements with other countries and did not fulfil them. As far as we are concerned, we are committed to the loan and we are having a programme....

श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी : मैंने ग्रापकी जानकारी के लिए कहा है कि खुसरु साहब के गध्ययन दल ने यह सिफारिश की है।

SHRI P. C. SETHI: I am coming to it. Please wait till I have finished, and if you have any questions, kindly raise them afterwards.

As far as the Khusro Committee's recommendations are concerned, more or less the Government have accepted all those recommendations. One of the recommendations was that when the PL-480 commodities' import actually stops, the PL-480 funds would be inflationary; otherwise they have said that they would be neither inflationary nor deflationary, because they are a part of the budget. When they are a part of the budget, when the commodities under PL-480 would stop coming, to that extent the expenditure out of the PL-480 funds would be inflationary. But even then, when we would make any expenditure out of the PL-480 funds as part of the budget, then, to that extent, we will have to raise the resources too. Supposing we draw Rs. 100 crores in the budget from the PL-480 funds, to the extent that we raise resources worth Rs. 100 crores, to that extent, it would not be inflationary. From this point of view, we will have to take into account expenditure which we make under PL-480 funds so that they do not work inflationarily in our total expenditure.

So far as the amount which accrues to the United States for their expenditure and the amounts which are in the Government securities are concerned, the Khusro Commimittee said, "Why not freeze them." The actual position remains thus: whatever amount is deposited in the Government or has been given to the Government as part of the loan or as part of the securities, it is actually frozen, and it has to be repaid according to the terms of the agreements. The terms of the recent loan agreements are that for the first ten years no amount is to be repaid, the rate of interest being two per cent. But after 10 years, it has to be repaid in equal instalments in 30 years, the rate of interest being three per cent. To that extent, the entire repayment is phased. At the same time, whatever money the United States Government uses, that money is to be spent in a manner that it also does not work in an inflationary way.

The hon. House is aware that recently under an agreement between the two countries, Rs. 105 crores out of this amount has been taken as part of the electrification programme and that has been agreed to. It was also said by the Prime Minister, as has been stated by the hon. Member Shri Samar Guha, that previously itwas not considered whether this amount could be spent for any slum clearance scheme or such things. But we are negotiating and we are trying to find out whether any such scheme could be made. I would not like to go into the details, but as far as the fourth Plan is concerned, Calcutta city has been amply taken care of; Rs. 42 crores have been provided during the fourth Plan period. This is an amount which is quite sumptuous as compared to the previous expenditure on Calcutta city. For instance, it was only Rs. 8 crores for the second Hoogly bridge. As compared to the previous expenditure of Rs. 13 crores to Rs. 14 crores during the Plan period, Calcutta Metropolitan City would be getting Rs. 50 crores during the fourth Plan period for various schemes. But I would not say that Rs. 50 crores is quite enough for the Calcutta city, because schemes have been worked out costing Rs. 120 crores to 200

crores for the Calcutta city. From that point of view, any agreement or scheme could be provided for slum clearance or things of that type. We are certainly working and negotiating on that basis. Therefore, so far as these funds are concerned, they would have to be spent in a manner which will not add to our inflation.

Shri Kanwar Lal Gupta raised a point about United States shipping. It is a fact that according to the agreement we have to bring 50 per cent of the total imports under PL 480 by the ships of the United States. At the same time, it is also provided that if the rates of the American companies are higher than the inter-national rates then to that extent they will be subsidised by the US. So, the agreement provides a cushion. Also, only 50 per cent is to be brought by the United States ships.

Shri Tyagi raised the point that the commodities coming under PL 480 and the money which has been given to the United States Embassy is being misused. This question was also raised by other hon. Members. As to how the money is being spent by the United States Embassy, we have no control over it. But, at the same time, I would like to make it very clear that 87 per cent of the PL 480 funds come to the Government in the form of loans or grants. About 5 per cent goes to the Cooly funds which are being used for giving loans to joint ventures. There are hundreds of such companies and Rs. 75 crores have been disbursed to them. According to the latest agreements, it is only 8 per cent of the amount that goes to the United States Government for their use. Out of this 8 per cent, according to the agreements 5 per cent could be converted, although it has not been fully converted as yet. Loans given to countries like Nepal also comes out of this 8 per cent. The expenditure of the United States Embassy is also covered out of this 8 per cent. If any donations or any help is to be given to any institution, that also comes out of this 8 per cent. For example, some of the institutions which have received assistance out of this 8 per cent are Holy Family Hospital, Christian Medical College and Hospital, Ludhiana, St. Johns Medical College and Hospital, Bangalore, Creighton-Freeman Christian Hospital, Vrindavan, Mercy Hospital, Jamshedpur, Miraj Medical Centre, Kasturba Hospital, Sevagram and Rajendra Memorial Research Institute, Patna. Therefore, for purposes of building and equipment this money could be given to such types of institutions.

At the same time, it is also stipulated that the end use of this money would not be for sectarian purposes. We take care of that.

Besides these moneys which the United States Embassy or the United States Government has got as part of the 8 per cent accural from PL 480 funds, there are certain PL 480 imports which are distributed free as charitable donations of commodities by certain institutions. From that point of view, it is for the Intelligence Department to find out as to what exactly is the end use of that commodity or money. When a Private Member's Bill was being moved in this connection, the hon. Home Minister requested the mover to withdraw the Bill and assured him that the Government is considering that a comprehensive Bill should be brought whereby foreign finance, whether in the form of cash or commodities, is not given to private individuals or institutions in a manner whereby it is used in a secterian manner or for political purposes.

श्री रवि राय (पुरी) : क्या इस सत्र में आप वह बिल लायेंगे ?

SHRI P. C. SETHI: That is for him to decide. Therefore, that has been taken care of.

As far as the control of the expenditure of the United States Embassy is concerned, I would like to point out that the Government of India cannot go into the detailed expenditure of the Embassy, be it that of USA or USSR. . . (*interruptions*) If out of this money any cash assistance to any institutions is given, that is with the Government's approval. For example, Rs. 105 crores are going to be spent for rural electrification. That is with Government's approval. But we have no control over whatever is the actual expenditure of the United States Embassy out of these funds as we have no control over other embassies. For example we have rupee trade with Yugoslavia, Czechoslovakia

[Shri P. C. Sethi]

or USSR. Those countries also get money in the form of Indian currency. Whatever they get in the form of that money is being spent for the embassies and we have no control over that because according to the convention it is not possible for us to go into the detailed expenditure or audit the accounts of these embassies.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will you make an amendment in the existing agreement? Will you scrap it or give an assurance that no further agreements will be made under PL-480?

SHRI P. C. SETHI: I have made the position clear as far as the food imports are concerned. The agreement is for the import of certain things; it is not forced on us. For example, we require cotton and for the purpose of that we have to enter into an agreement.

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा कहना यह है कि जैसे शिपिंग के बारे में कंडीशन है कि 50 परसेंट ग्रमरीकन जहाज से होगा, वह हटा दिया जाय । इस तरह की जो शर्तें हमारे खिलाफ हैं उनमें ग्राप तरमीम करेंगे ?

SHRI P. C. SETHI: As far as shipping is concerned, it is a part of the agreement. I am thankful to the hon. Member for making a very good suggestion. But these agreements are mutually drawn agreements and it cannot be done unilaterally.

श्री रवि राय : जो राष्ट्र के हित में नहीं है उसको तो हटा सकते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : ग्रायल कंपनीज में ग्रापने किया है ।

श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी : मंत्री जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि ग्रमरीका की सीनेट के दो ग्रादमियों ने चार्ज लगाया है कि भारत सरकार ने हमारे सामने कोई स्कीम पेश नहीं की ।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till Eleven o'clock tomorrow.

19.13 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 2, 1970, Chaitra, 12, 1892 (Saka).